श्रम विभाग

ग्रादेश

दिनांक 5 दिसम्बर, 1985

सं० ग्रो०वि०/एफ०डी०/266-85/49297.—चृंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० ग्रजीत इण्डस्ट्रीज, प्लाट नं० 43 ई डी०एल०एफ० एरिया, मथुरा रोड़, फरीदाबाद, के श्रीमक श्री मांगी लाल ग्रग्रवाल तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई ग्रौद्योगिक विवाद है;

श्रीर चं कि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना बांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, श्रीद्योगिक विवाद प्रधिनियम 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदाक की गई शिक्तयों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी श्रिधसूचना सं० 5415-3-श्रम-68/15254, दिनांक 20 जून, 1968, के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं० 11495-जी-श्रम/57/11245, दिनांक 7 फ़रवरी, 1958, द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, फरीदाबाद, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायिनर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है:---

क्या श्री मांगी लाल ग्रग्रवाल की सेवाग्रों का समापन त्यायोचित तथा ठीक है? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है? सं० ग्रो०वि०/यमुना/49303.—चूंकि हरियाणा राज्यपाल की राय है कि मै० भूटानी ट्रांसपोर्ट, जगाधरी, के श्रमिक श्री कैलाश चन्द तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई ग्रौद्योगिक विवाद है;

ग्रीर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना बांछनीय समझते हैं;

इसलिए, ग्रब, ग्रौद्योगिक विवाद ग्रिधिनियम, 1947, के नरा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शिवतयों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी ग्रिधिसूचना सं० 3(44)84-3-श्रम, दिनांक 18 अप्रैल, 1984, द्वारा उनते ग्रिधिनियम की धारा 7 के ग्रधीन गठित श्रम न्यायालय, ग्रम्बाला, को विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाद तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उनत प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उससे सुसंगत ग्रथवा सम्बन्धित मामला है:—

ग्रौर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं;

इसलिए, अब, अौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचनी स० 3 (44) 84-3-अम, दिनांक 18 अप्रैल, 1984, द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, अम्बाला, को विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उससे सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है:—

वया श्री रमेश कुमार की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है? यदि नहीं, तो वह विस राहत का हकदार हैं?
संज्ञोिजिव श्रम्बाला / 130-85 / 49315.--चूं कि हिरयाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं ० (1) पिबहन आयुद्दत,
हरियाणा, चण्डीगढ़, (2) जनरल मैनेजर हरियाणा रोडवेज अम्बाला, के श्रमिक श्री अनिरुध कुमार तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य
इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई आधोगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं :

इसलिए, अब, श्रौद्योगिक विवाद श्रधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शित्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी श्रिधिसूचना सं० 3(44)-84-2-श्रम, दिनांक 18 श्रप्रैल, 1984, द्वारा उक्त श्रिधिनियम की धारा 7 के श्रधीन गठित श्रम न्यायालय, श्रम्बाला, को विवादशस्त या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवाद प्रस्त मामला है या उससे सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है:—

क्या श्री ग्रनिरुध कुमार की सेवाग्रों का समापन न्यायोचित तथा ठीक है? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है?